Sixth Economic Census in Delhi begins

Special Correspondent

NEW DELHI: Chief Minister Sheila Dikshit on Thursday launched the sixth Economic Census in Delhi by furnishing her details to the enumerator who visited her official residence for collecting the information and filling up the schedules for recording details of the households and establishments.

Speaking on the occasion, Ms. Dikshit urged all Delhi citizens to extend their full cooperation in furnishing accurate and complete information during the 6th Economic Census.

She said this census would result in complete enumeration of all establishments/units performing economic activities within the geographical boundaries of Delhi. Over February and March, about 12,000 enumerators and supervisors will carry out the census in about 33,200 enumeration blocks spread over the 11 revenue districts of Delhi.

Chief Minister Sheila Dikshit launching the Sixth Economic Census in Delhi on Thursday by furnishing her details to Dr. B. K. Sharma, Director, Directorate of Economics & Statistics, at her residence. PHOTO: SANDEEP SAXENA

The field survey is expected to cover around 45 lakh census households. The earlier surveys were conducted in 1977, 1980, 1990, 1998 and 2005.

Apart from data from the organised sector, the Economic Census would also seek to capture the data in respect of the unorganised sector which plays an important role in Delhi's economy.

The Hindu
22/1/2013

PROVIDING THE FLAT, WHICH WOULD BE WORTH ₹50 LAKH

for cabinet approval
The issue of allotting
the victim's family,

omic activities which

epreneurs from home
decisions.
onomic census.

equisite information to
signment of National

ial and utilized only for

th the statutory support
ormation, making false
able under the Act.

act us at

DIP/2167/2012-13

my delhi
I Care

6TH ECONOMIC CENSUS BEGINS

NEW DELHI: Delhi Chief Minister Sheila Dikshit launched the sixth economic census on Thursday with the enumerator visiting the CM's official residence for collecting information and filling up the schedules for recording details of the households and establishments.

About 12,000 enumerators and supervisors will carry out the census in about 33,200 enumeration blocks spread in the 11 districts of the city between February and March. The field survey is expected to cover around 45 lakh census households.

"The economic census emerges as the only source of information in respect of unorganised sector," said a senior Delhi government official. The economic census will also provide information in respect of establishments having no fixed premises such as mobile vendors, hawkers, rickshaw pullers, taxi and auto rickshaw operators, reheriwalas, cobblers, etc. **HTC**

A first doorst

Hamari Jamatia
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: For the first ... dents of East Delhi w... daily household w... collected from their... free of cost.

In a bid to strea... garbage managem... tem, the East Delhi... Corporation has ti... an NGO named Ch... will employ ragpicke... garbage from door t... segregate them.

Under this, a pilo... two wards — Kisha... Bhrampuri — is e... start during this we...

The ragpickers... every morning to c... bage, which will be t... to a facility where s... will take place. The... dissuade people fro... garbage on the stre... as to allow ragpicke... the garbage directly...

Hindustan times, 22/2/13

22/2/2013

ल्ली

विकसित होंगे
रिडोर: एलजी

इसके लिए जगह-जगह सेमिनार आयोजित कर लोगों की राय ली जाएगी। सेमिनार में आए मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में मेट्रो के चार कॉरिडोर चिन्हित किये गये हैं। पीरागढ़ी से टीकरी कलां,

छतरपुर से अर्जुन पुर, द्वारका से द्वारका सेक्टर-9 और नेहरू प्लेस से बदरपुर का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कड़कड़डूमा को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। इसके आसपास के दो किलोमीटर के क्षेत्र को टीओडी के तहत विकसित किया जाएगा। यूटीपैक के सदस्य सचिव अशोक चटर्जी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर दिल्लीवासियों से रायशुमारी की जाएगी। इसके लिए सेमिनारों का दौर शुरू हो चुका है। इस पॉलिसी को आने वाले दिनों में दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में शामिल किया जाएगा।

दीक मिक्स लैंड यूज
हुमंजिला इमारतें
ट्रो कॉरिडोर चिन्हित,
लट प्रोजेक्ट

क्या है टीओडी : डीडीए की उपनिदेशक रोमी रॉय ने बताया कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के तहत मेट्रो एवं बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी) कॉरिडोर के आसपास के दो किलोमीटर के क्षेत्र को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाएगा। यहां रिहायशी भवनों के साथ-साथ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कॉरपोरेट बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। यहां स्कूल, अस्पताल व पार्क जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ताकि लोगों को अधिक दूर तक सड़क पर पैदल न चलना पड़े।

राजधानी में छठी आर्थिक गणना शुरू

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में बृहस्पतिवार से छठी आर्थिक गणना की शुरुआत हुई। इसमें लगे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंच कर अभियान का शुभारंभ किया। इस गणना के तहत राजधानी के 45 लाख परिवारों से उनके व्यवसाय, आर्थिक स्तर व जीवन शैली के बारे में जानकारी ली जाएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नागरिकों से अपील की है कि वह इस गणना के लिए सही और पूरी जानकारी में सहयोग दें तथा गणना को कामयाब बनाएं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों और इकाइयों से जानकारी ली जाएगी। दिल्ली के 11 राजस्व जिलों में फरवरी से मार्च के बीच 33,200 गणना खंडों में कर्मचारी और निरीक्षक काम करेंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक और गणना के मुख्य आयुक्त वीके अरोड़ा और योजना विभाग के निदेशक डॉ. बी.के. शर्मा भी मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे।

प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए बिल्डर का खाता अटैच

नई दिल्ली (एसएनबी)। साउथ एमसीडी ने एक जाने माने बिल्डर की छह संपत्तियों के खाते अटैच किए हैं। बिल्डर पर नगर निगम का कुल 92.59 लाख रुपए बकाया है। उपरोक्त सभी संपत्तियां दक्षिणी दिल्ली स्थित एंड्रयूज गंज में हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि उनके किराये से नगर निगम बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की भरपायी करेगा। नगर निगम के मुताबिक सभी छह संपत्तियां व्यावसायिक हैं और अंसल प्रॉपर्टी एण्ड इंफ्रास्ट्रेक्चर के नाम पर हैं। मार्च, 2012 तक उनके ऊपर 92,59,736 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। निगम ने बैंक खाता अटैच कर लिया है।

डीयू : परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि फिर बढ़ाई

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी 28 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। अभी हाल ही में विश्वविद्यालय ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर 19 फरवरी किया था, लेकिन 19 फरवरी तक भी कुछ विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सके। ये स्टूडेंट्स भी फार्म भर सकें, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। सबसे पहले अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई थी।

बसंतोत्सव

कास स्कूल ने बृहस्पतिवार को मलाल गर्ग व निगम पार्षद रेनू उप शिक्षा निदेशक पीसी बोस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य न, स्टेट व जोनल लेवल पर वार्ड से नवाजा। इस मौके पर क कार्यक्रम पेश किया गया।

म स्कूलों
यूनिफॉर्म

पर्वतीय कला केन्द्र
स्थापित 1968

अपनी नवीनतम प्रस्तुति शैलेश मटियानी की दो चर्चित कहानियों लोक देवता एवं बर्फ की चट्टानें पर आधारित संगीतमय नाटक

कथा शैलेश

के मंचन पर आपको सादर आमंत्रित करता है।

संगीत – भगवत उप्रेती
निर्देशन – अमित सक्सेना

प्रदर्शन तिथि – 22, 23 एवं 24 फरवरी 2013, प्रतिदिन सायं 6.30 बजे

एल. टी. जी. सभागार,
कोपरनिक्स मार्ग, (मंडी हाऊस) नई दिल्ली – 110001

प्रवेश निःशुल्क
पूछताछ : 22734840, 22756217, 9810304320

दो लोगों ने फांसी लगाई

जासं, नई दिल्ली : यमुनापार में अलग-अलग इलाकों में दो लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खजूरी खास इलाके में अवसाद के शिकार 56 वर्षीय रमेशचंद शर्मा ने फांसी लगा ली, वहीं गाजीपुर में 35 वर्षीय ने हरिशंकर ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। रमेश चंद परिवार के साथ सादतपुर में रहते थे। परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। वह काफी समय से बेरोजगार थे। बुधवार शाम को जब वह घर में अकेले थे तभी उन्होंने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छानबीन में पता चला है कि रमेश करीब ढाई साल से अवसाद के शिकार थे। दूसरे मामले में हरिशंकर परिवार के साथ कोंडली में रहता था। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। बुधवार रात को हरिशंकर पत्नी और बच्चे के साथ कमरे में सो रहा था। सुबह जब उसकी पत्नी सोकर उठी तो उसने पति को फांसी पर लटके देखा। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

अरबों की सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, दिया धरना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : बटुकेश्वर (बीके) दत्त कॉलोनी में अरबों रुपयों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर कॉलोनी की वेलफेयर एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को जंतर-मंतर पर धरना दिया। इस मौके पर पूर्व सांसद बीएल शर्मा प्रेम ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो आमरण अनशन किया जाएगा।

जंतर-मंतर पर धरने पर विधायक करण सिंह तंवर, पूर्व विधायक रामभज, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार हरदेव सिंह धनोवा, राष्ट्रवादी शिवसेना प्रमुख जयभगवान गोयल, अखंड हिंदुस्थान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप आहूजा भी बैठे। इस मौके पर कालोनी वासियों ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि एवं विकास विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से यहां अवैध कब्जा हुआ है। लेकिन सरकार ने इस ओर से आंखें मूंद रखी हैं। कॉलोनी के पार्कों पर अवैध कब्जे को लेकर कालोनी वासियों ने भारी विरोध जताया। इस मौके पर सुरेश शर्मा, राजीव राणा, शैलेंद्र जैन, अनिल चौधरी, कर्मवीर सिंह नागर, सोहन लाल आदि मौजूद थे।

अवैध कब्जे के विरोध में जंतर मंतर पर धरना देते पूर्व सांसद बीएल प्रेम सहित बीके दत्त कालोनी के निवासी। जागरण

सरकारी स्कूलों में नहीं की जाती बच्चों की पिटाई

- दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दायर की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजधानी के किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षकों द्वारा छात्र-छात्राओं की किसी भी तरह से पिटाई नहीं की जाती। न ही बच्चों को किसी अन्य तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। यह बात दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से कही है। यह रिपोर्ट सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षकों द्वारा पिटाई के मामले को लेकर दायर की गई याचिका के संबंध में अदालत के समक्ष दी गई है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन व जस्टिस वीके जैन की खंडपीठ ने उक्त मामले में सरकार को निर्देश दिया कि वह अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव के समक्ष रखे। शिक्षा सचिव इस रिपोर्ट को शिक्षा निदेशक की मदद से जांचें और फाइनल रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाए। अब इस मामले की सुनवाई एक मई को होगी। दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने कहा कि जांच में किसी भी स्कूल में शिक्षक द्वारा बच्चों को पीटने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी जरूर है।

उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दिल्ली सरकार व नगर निगम के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के नाम पर राजधानी के विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा लिखे गए 181 पोस्ट कार्ड प्राप्त हुए हैं। जिनमें छात्रों ने बताया है कि उन्हें स्कूल में शिक्षकों द्वारा स्टिक, सैंडल व चप्पल से पीटा जाता है। साथ ही स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति में बहुत कम है। कुछ स्कूलों में शिक्षकों द्वारा छात्रों को मुर्गा बनाकर पिटाई की जाती है। कुछ स्कूलों में बीस बेंच वाले कक्षा में छात्रों की संख्या 140 तक है। शौचालयों एवं अन्य जनसुविधाओं की हालत भी खराब है, जबकि शिक्षकों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि बच्चों की पिटाई के मामले में पहले ही दिल्ली सरकार व उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा चुकी है। फिर भी इन आदेशों का असर सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर नहीं हुआ है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था।

उत्तरी जिला सब्जीमंडी इलाके से व्यवसायी लापता

जासं, नई दिल्ली : उत्तरी जिला सब्जीमंडी इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में व्यवसायी लापता हो गया है। तिलक नगर निवासी सन्नी गुप्ता ससुराल वालों से नाराज चल रहे हैं। तीन दिन पहले उन्होंने अपने चचेरे ससुर को मोटरसाइकिल की चाबी और एक पत्र सौंपा था। पत्र में लिखा है कि वे अपने सास-ससुर से तंग आकर खुदकुशी करने जा रहे हैं। पुलिस ने लापता होने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक व्यवसायी का कोई सुराग नहीं मिला है। सन्नी 19 फरवरी को उत्तरी जिला सब्जी मंडी स्थित अपने ससुराल गए थे। वहां उनकी मुलाकात चचेरे ससुर से हुई थी।

मुख्यमंत्री ने छठी आर्थिक गणना की शुरुआत की

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बृहस्पतिवार को अपने निवास स्थान से छठी आर्थिक गणना की शुरुआत की। गणना में लगे कर्मचारियों ने सबसे पहले शीला दीक्षित से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से इस गणना के लिए सही और पूरी जानकारी देने व इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में मदद देने की अपील की। इसके तहत दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों और इकाइयों से जानकारी हासिल की जाएगी।

दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के 11 राजस्व जिलों में फरवरी से मार्च के बीच 33,200 गणना खंडों में कर्मचारी और निरीक्षक काम करेंगे। इस गणना के तहत 45 लाख परिवारों से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 1977, 1980,1998 और 2005 में आर्थिक गणना कराई गई थी।

मुख्यमंत्री से जानकारी हासिल करने के मौके पर अतिरिक्त महानिदेशक व गणना के मुख्य आयुक्त वीके अरोड़ा और दिल्ली सरकार के योजना विभाग के निदेशक बीके शर्मा भी मौजूद थे। गणना में असंगठित क्षेत्र के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, जिसकी दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। फेरीवाले, रिक्शा-ऑटो टैक्सी चालकों, रेहड़ीवालों, कुलियों, इलेक्ट्रीशियन आदि काम करने वाले लोगों के बारे में इस गणना के तहत जानकारी हासिल की जाएगी।